

पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 116/16

अपीलांट

मृत कन्हैयालाल उर्फ कनाराम पुत्र गोकुलजी जाति पालीवाल निवासी भांगेसर के वैध कायम मुकामात—

1. मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल उर्फ कनाराम
2. मथुरादेवी पत्नी कन्हैयालाल उर्फ कनाराम जातिगण पालीवाल निवासीगण भांगेसर तहसील पाली (राज.)
3. श्रीमती हुलियादेवी पुत्री कन्हैयालाल उर्फ कनाराम पत्नी किशनजी जाति पालीवाल निवासी काकेलाव जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. बाबुलाल पुत्र शंकरलालजी जाति पालीवाल निवासी निम्बली ब्राह्मण तहसील रोहट
2. मुसम्मात सूरजा बेवा देवाजी जाति पालीवाल निवासी निम्बली ब्राह्मण तहसील रोहट
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



उपस्थित :-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक : 27.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,

पेज संख्या 2/4

92ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 284 एवं 304 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अपीलांट के जवाब हेतु नियत था। इस दौरान प्रतिवादीगण के वकील ने न्यायालय में जाहिर किया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर अधिवक्ता वादी ने वादी के पते पर रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया, जिस पर वारिसान द्वारा आकर मृत्यु होने का कथन करने पर वादी अपीलांट की ओर से आदेश 22 नियम 3 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ ही विलम्ब के शमन हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत आवेदन मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली उपरोक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत थी एवं पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 08.02.2016 नियत की गई थी। इसी दौरान पत्रावली को बिना वादी/अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किये दिनांक 08.06.2016 को कैम्प कोर्ट भांगेसर में प्रस्तुत होना बताते हुए अपीलांट के आदेश 22 नियम 3 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया एवं उसके आधार पर वाद को एबेट मानकर वाद खारिज कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकी में जाकर प्रकरण को एबेट के आधार पर खारिज किया है, जबकि वादी की मृत्यु की जानकारी अधिवक्ता वादी को होना संभव नहीं है एवं न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से पेशी दिनांक 14.05.2014 को वादी की मृत्यु होना न्यायालय में जाहिर किया, जिस पर वादी के पते पर दिनांक 15.05.2014 को ही रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया गया। उपरोक्त नोटिस वादी/अपीलांट के परिजनो को मिलने के पश्चात उनके अधिवक्ता से संपर्क किया गया, जिस पर बिना कोई देरी किये ही दिनांक 27.05.2014 को आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 5 के आवेदन मय शपथ-पत्र पेश कर दिये थे, इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी से 10 दिन के अंदर-अंदर आवेदन पेश कर दिया था, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य था। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेकानेक निर्णयो मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मयाद के आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए एवं मयाद पर किसी प्रकरण को निर्णीत करते समय प्रकरण को गुणवागुण पर देखा जाना आवश्यक होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को दरकिनार करते हुए लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निर्णीत मुकदमों की संख्या बढ़ाने की नियत से बिना पक्षकार को सूचना दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन 22 नियम 3 स्वीकार करते हुए कायम मुकाम रेकॉर्ड पर लिया जाकर वाद पुनः विधिअनुसार निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली रिमांड की जावे।



उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 3/4

अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी ग्राम भांगेसर के खसरा नंबर 284 एवं 304 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एबेट होने से खारिज किया गया है। इस संबध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 तहत विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम के खण्ड द्वितीय के भाग 1 के नियम 120 के तहत किया जाना आज्ञापक है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये परिसीमित समय 90 दिवस नियत किया है, जिसकी संगणना यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से की जानी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2005 (2) पेज 929 में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश 22 नियम 3 वादी के विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन - अपीलाण्ट के पिता ने वाद पेश किया, किन्तु अपील के विचाराधीन होने के तथ्य से अपीलाण्ट अनभिज्ञ था - एडवोकेट के पत्र से अपीलाण्ट की जानकारी में तथ्य आया - कालबाधित होने से आवेदन खारिज किया गया तथा उपशमन अपास्त करने व विलम्ब माफ करने का अनुतोष नहीं चाहा-तकनीकी आपत्तियां रास्ते में नहीं आनी चाहिये - आदेश अपास्त किया तथा विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। इसी प्रकार एस0सी0आर0 2010 (8) पेज 597 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Code of Civil Procedure, 1908 - Order 22, rules 3 and 9; s. 151 read with s.5 of Limitation Act, 1963 - Death of appellant during pendency of appeal before Supreme Court - Application filed after long delay of 778 days for bringing the legal representatives of deceased appellant on record accompanied by application for condonation of delay - Held: Such applications cannot be allowed as a matter of right and even in a routine manner - They should be rejected unless sufficient cause is shown for condensation of delay - On facts, except for a vague averment that the legal representatives were not aware of the pendency of the appeal, no other justifiable reason was stated by the applicants - The applications also did not contain correct and true facts, thus, want of bona fides is imputable to the applicants - No reason nor sufficient cause was shown as to why immediate steps were not taken by the applicants, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal - The conduct of the



राजस्थान अपील प्रक्रिया संहिता
जयपुर

applicants was abnormal - They acted irresponsibly and even with negligence, and miserably failed in showing any 'sufficient cause' for condonation of the long delay of 778 days - Applications accordingly dismissed - Resultantly, the appeal, having already abated, also dismissed.

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रामनाथ साआ एल्यास रामनाथ साओ एण्ड अदर्स बनाम गोवर्धन साओ एण्ड अदर्स (2002)3 एस.सी.सी. पेज 195 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The expression "sufficient cause" within the meaning of Section 5 of the Act or Order 22 Rule 9 of the Code or any other similar provision should receive a liberal construction so as to advance substantial justice when no negligence or inaction or want of bona fide is imputable to a party. In a particular case whether explanation furnished would constitute "sufficient cause" or not will be dependent upon facts of each case. There cannot be a straitjacket formula for accepting or rejecting explanation furnished for the delay caused in taking steps. But one thing is clear that the courts should not proceed with the tendency of finding fault with the cause shown and reject the petition by a slipshod order in over jubilation of disposal drive. Acceptance of explanation furnished should be the rule and refusal an exception more so when no negligence or inaction or want of bona fide can be imputed to the defaulting party. On the other hand, while considering the matter the courts should not lose sight of the fact that by not taking steps within the time prescribed a valuable right has accrued to the other party which should not be lightly defeated by condoning delay in a routine like manner. However, by taking a pedantic and hyper technical view of the matter the explanation furnished should not be rejected when stakes are high and/or arguable points of facts and law are involved in the case, causing enormous loss and irreparable injury to the party against whom the lis terminates either by default or inaction and defeating valuable right of such a party to have the decision on merit. While considering the matter, courts have to strike a balance between resultant effect of the order it is going to pass upon the parties either way." इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 885 में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय की गलती के लिये पक्षकार पीड़ित नहीं हो सकता—विचारण न्यायालय ने बहुत ही अधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया—निर्णीत, आवेदन स्वीकार किया और विधिक वारिशान को रेकार्ड पर लिया जावे।" हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 6 के फौत होना संज्ञान में आने के लगभग 125



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 5/5

दिनों के पश्चात अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा का0मु0 को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई 35 दिवस की अवधि को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये - तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।"

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय हित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुण के आधार पर तय किये जाएं। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को अपने हक से वंचित नहीं कराया जा सकता। कानूनन विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण में शामिल करने के लिए 90 दिन की अवधि प्राप्त है। इस अवधि में पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद का उपशमन स्वतः हो जाता है। लेकिन उक्त प्रावधान बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक प्रावधान है, जिन्हे न्यायालय सन्तुष्ट होने पर प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए छूट दे सकता है तथा विलम्ब की अवधि को क्षमा कर सकता है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि मात्र तकनीकी आपत्ति के आधार पर अपील को उपशमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पक्षकारों को रिकार्ड पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिये, जिससे पक्षकारों को पूर्ण न्याय मिल सके। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये केवल मात्र तकनीकी आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशासित प्रवृत्ती)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली